डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जुलाई, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 जुलाई, 2020

| वर्ष 64 | अंक 04 | भोपाल | 16 जुलाई, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

गेहूँ उपार्जन में रिकार्ड के बाद मध्यप्रदेश अब सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकार्ड बनायेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वी.सी. से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हो रहे है। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के साथ ही मध्यप्रदेश ने गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन किया है। अब मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में भी रिकार्ड बनायेगा। शासन ऐसी योजना बना रहा है, जिसके माध्यम से अब किसान अपनी बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकेगा। वह स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही दूसरों को भी बिजली दे पायेगा। हमारा अन्नदाता किसान अब ऊर्जादाता भी बन सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल लखनऊ से, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री थावरचंद गहलोत, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री प्रहलाद पटेल, श्री आर. के. सिंह, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते दिल्ली से तथा रीवा से सांसद, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

दिल्ली मेट्रो रीवा से चलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रीवा सोलर परियोजना से न केवल मध्यप्रदेश को बिजली प्राप्त हो रही है बल्कि यह हर्ष का विषय है कि परियोजना अपनी 24 प्रतिशत बिजली दिल्ली मेट्रो को प्रदान कर रही है। दिल्ली की मेट्रो रीवा से चलेगी।

श्योर, प्योर एवं सिक्योर ऊर्जा का स्त्रोत है सूर्य

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में सूर्य उपासना का विशेष स्थान है। सूर्य हमें पवित्र तो करता ही है, हमारे लिये अक्षय ऊर्जा का स्त्रोत भी है। सूर्य श्योर, प्योर एवं सिक्योर ऊर्जा देता है। इसकी ऊर्जा ''श्योर'' अर्थात सदा सर्वदा है, ''प्योर'' अर्थात पर्यावरण के लिये सुरक्षित एवं शुद्ध है तथा ''सिक्योर'' अर्थात हमेशा के लिये है और हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की क्या जरूरत है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ''स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना'' एवं ''ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल'' का शुभारंभ किया

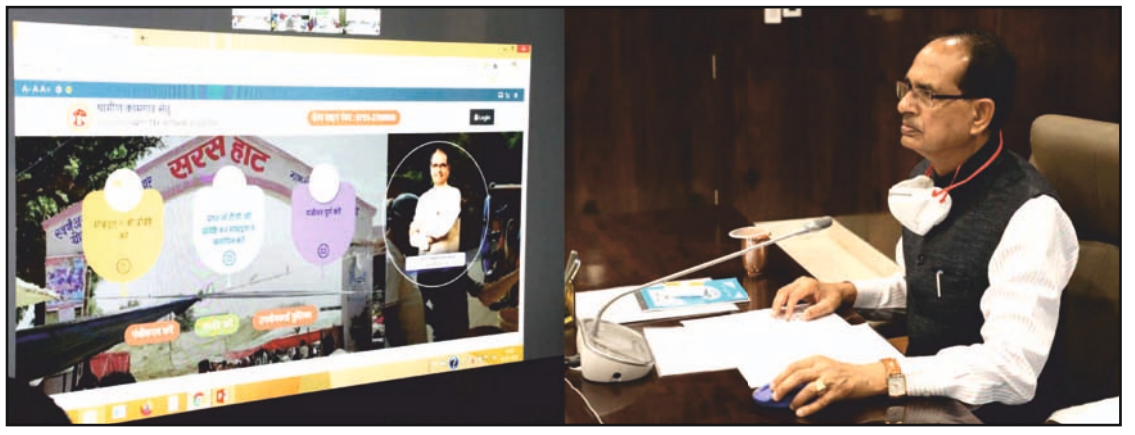

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब सरकार है तो जनता को काम–धंधे के लिए ऋण के लिये साहूकारों के पास जाने की क्या आवश्यकता है। सरकार अब शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की तरह ही ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनके कार्य एवं व्यवसाय के लिए 10 हजार की कार्यशील पूंजी बैंकों से बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। ब्याज की राशि राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए हितग्राहियों द्वारा बैंक को किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि नहीं देनी होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में ''मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना'' तथा ''ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल'' का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

जाति का कोई बंधन नहीं

योजना शुभारंभ के पश्चात ग्रामीण पथ विक्रेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में जाति, शैक्षणिक योग्यता आदि का कोई बंधन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 55 वर्ष के पथ विक्रेता इस योजना का लाभ ले सकेंगे। केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक, बढ़ई, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलर, कर्मकार मंडल से संबंधित कामगार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

30 दिन के अंदर बैंक करेगी ऋण स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर बैंक द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाएगा। प्रकरणों का निराकरण ''पहले आओ–पहले पाओ'' के आधार पर होगा। योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाएगी तथा जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर होगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदक कामगार सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा होगी।

कोई शुल्क प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि जमा नहीं करानी होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रतिभूति अथवा धरोहर राशि जमा नहीं करानी होगी।

प्रदेश के लिये 5.75 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की मांग

मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के लिए अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया। श्री चौहान ने कुल 5.75 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया राज्य के लिए शीघ्र आवंटन करने की मांग की। श्री चौहान ने बताया कि माह जुलाई के लिए डेढ़ लाख मीट्रिक टन यूरिया और अगस्त से सितम्बर तक के लिए 4.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया आवंटन की आवश्यकता है। केन्द्रीय मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने राज्य को अतिरिक्त यूरिया का कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया और साथ ही प्रदेश में रैक प्वाइंट्स बढ़ाने की सहमति दी।

उल्लेखनीय है कि खरीफ 2020 के लिए केन्द्र सरकार ने 11 लाख मीट्रिक टन यूरिया देने पर सहमति जतायी थी। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक वर्षा हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप 72 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की बुआई हो चुकी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित दो पुस्तिकाओं– 'उम्मीद' और 'मध्यप्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास' की प्रतियाँ भेंट कीं।

मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग दिलाने का अनुरोध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर से मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग दिलवाने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन 13 जिलों में किया जाता है और इससे प्रदेश के लगभग 80 हजार किसान जुड़े हुए हैं। किसानों के हित और चावल की गुणवत्ता को देखते हुए मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जी.आई. टैग देना उचित होगा।

श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश का चावल यहां के किसानों द्वारा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जिससे लगभग तीन हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष आती है। मध्यप्रदेश के 13 जिलों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में उत्पादित होने वाले चावल को बासमती टैग न दिये जाने से किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह अभी नहीं मिल पा रहा है।

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भण्डार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती हैं।

— अब्दुल कलाम

गरीबों के लिए पूरा पैकेज है संबल योजना

किसी भी सरकार का धर्म है कि जो गरीब है, दीन है, दुखी है, पिछड़े है उनको विशेष सुविधाएँ दी जाये। महात्मा गांधी लगातार कहते थे कि सरकार का पहला काम निर्धनों की सेवा है। पूज्य डॉ. हेडगेवार ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। मध्यप्रदेश सरकार इन्हीं महापुरूषों के बताये रास्ते पर चल रही है। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में ही शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना को फिर से शुरू किया गया। फिर से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि पिछले सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते मे डाल दिया था।

कोरोन संकट के बीच महामारी से जूझ रहे लोगों की जिन्दगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल, गरीब जनता की जिंदगी में नये प्रकाश के रूप में आयी है। संबल केवल योजना नही है बल्कि गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, माँ, बहन, बेटियों का सशक्तिकरण है संबल। जीवन की कठिन लड़ाई में ऐसे गरीब भाई बहनों जो आर्थिक रूप से संपन्न नही है उन्हें सहारा चाहिए, साथ और सहयोग चाहिए। संबल योजना इसीलिए लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीबों को न्याय मिल रहा है, यही सामाजिक न्याय है।

संबल योजना में पहले कार्ड बने थे। योजना शुरू होते ही सभी पंजीकृत हितग्राहियों को लाभ मिलने लगा। संबल योजना ऐसी है जो जन्म से जीवन पर्यन्त तक हितग्राहियों को लाभ पहुँचाती है। संबल योजना के पात्र बहन को बेटा, बेटी जन्म देने के पहले 4 हजार रूपये और जन्म देने के बाद 12 हजार रूपये उनके खाते में दिये जाते है। यह सहायता बहनों को आराम करने का अवसर देती है और पोषण आहार भी मिलता है। इस योजना में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के मामा कहे जाते हैं। संबल में पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किताबें, आठवीं तक यूनिफार्म् और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था रहती है। मुख्यमंत्री ने एक नई योजना इसमें जोड़ी है, संबल परिवार के ऐसे बच्चे जो 12वीं में मेरिट में आते है ऐसे 5 हजार बच्चों को 30 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी अलग से दिये जायेगें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान का कहना है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में गरीब बच्चों का चयन हो जाता है तो फीस भरना उसके बूते की बात नही हैं, इसलिए सरकार फीस की व्यवस्था करती है। पढ़ाई के साथ ही खेल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत संबल परिवार के बच्चों जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे उन्हें 50 हजार प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है।

संबल योजना में गरीबों को सस्ते दर पर बिजली तथा बीमारी के लिए सहायता भी दी जाती है। पंजीकृत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की राशि परिवार के सहारे के लिए दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये की व्यवस्था संबल में की जाती है। आंशिक स्थाई अपंगता पर भी आर्थक सहायता संबल के तहत मिलती है। संबल गरीब के लिए एक पूरा पैकेज है, ऐसी योजना देश में किसी भी राज्य में नही हैं।

प्रदेश में 99 लाख हेक्टेयर से अधिक में हुई बुआई

भोपाल। खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रदेश में द्रुत गति से जारी है। प्रदेश में अब तक 99 लाख 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष 146 लाख 31 हजार क्षेत्र में बुआई के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 68 प्रतिशत की बुआई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश में खरीफ फसलों में धान, दलहन और तिलहन की बुआई का कार्य किया जा रहा है। अब तक 13 लाख 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 8 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 85 हजार हेक्टेयर में ज्वार, एक लाख 48 हजार हेक्टेयर में बाजरा और 36 हजार हेक्टेयर में कोदो–कुटकी व अन्य खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। दलहन में 11 लाख 42 हजार हेक्टेयर में उड़द, 2 लाख 65 हजार हेक्टेयर में तुअर, 91 हजार हेक्टेयर में मूँग, 10 हजार हेक्टेयर में कुलथी और अन्य दलहन की बुआई की गई है। अब तक 51 लाख 17 हजार हेक्टेयर में सोयाबीन, एक लाख 75 हजार हेक्टेयर में मूँगफली, एक लाख 19 हजार हेक्टेयर में तिल और 6 हजार हेक्टेयर में अन्य तिलहन फसलों की बुआई की गई है। इसी प्रकार 5 लाख 87 हजार हेक्टेयर में कपास की बुआई भी हो चुकी है।

प्रवासी मजदूरों को वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत नवम्बर माह तक राशन मिलेगा

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान के निवास पर मुलाकात कर गेहूं उपार्जन, बोनस और प्रवासी मजदूरों के राशन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 73.70 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा गेहूं उपार्जित किया गया था जिसमें से केन्द्र सरकार ने 67.25 लाख मीट्रिक टन को ही केन्द्रीय पूल में मान्य किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया कि शेष 6.45 लाख मीट्रिक टन गेहूं को भी केन्द्रीय पूल में शीघ्र शामिल किया जाय, जिससे किसानों को इसका भुगतान किया जा सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को दिये जाने वाले राशन के संबंध में बताया कि प्रदेश में लगभग 13 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख 90 हजार मजदूरों के पास राशनकार्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं होने से उन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री राम विलास पासवान ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वासन दिया कि पिछले वर्ष का शेष उपार्जित गेहूं 6.45 लाख मीट्रिक टन को शीघ्र ही केन्द्रीय पूल में शामिल किया जायेगा। जिससे किसानों को इसका भुगतान शीघ्र किया जा सके। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को माह नवम्बर 2020 तक राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन–वन राशन कार्ड सिद्धांत के तहत सभी प्रवासी मजदूरों को जो जहां भी है उसको वहां राशन मिलेगा।

श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और साथ ही उनको जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

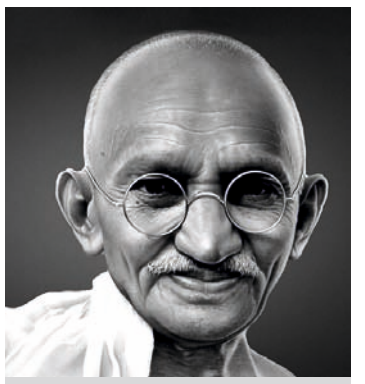

कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता हैं।

– महात्मा गांधी

किसानों ने महसूस की अपनी सरकार

किसानों का महानायक किसान पुत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ लेते ही कोरोना की संकटकालीन परिस्थितियों के मुकाबले के साथ अन्नदाता किसानों की सबसे पहले चिंता की। किसानों की फसल कट चुकी थी, 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाती थी। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तब–तक खरीदी प्रारंभ करने की कोई तैयारी नहीं थी। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे थी। कोविड–19 की भयावह तस्वीरों में किसान चिंतित थे कि इस बार उनका गेहूँ खरीदा भी जायेगा या नहीं। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी की प्रभावी तैयारियां की जिसके चलते प्रदेश में 15 अप्रैल से खरीदी प्रांरभ हुई। विपरीत परिस्थितियों में बेहतर तैयारियों और सतत मॉनिटरिंग से प्रदेश ने इस साल गेहूँ उपार्जन का ऑल टाईम रिकार्ड बनाया।

मध्यप्रदेश ने एतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गेहूँ उपार्जन के मामले में देश के अग्रणी राज्य के रूप में नई पहचान स्थापित की है। मध्यप्रदेश के अन्नदाता किसानों ने मध्यप्रदेश को बनाया है। पंजाब जो परंपरागत रूप से गेहूँ उत्पादन और उपर्जन में देश में सबसे आगे होता था वो स्थान आज मध्यप्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ उपार्जन कर मध्यप्रदेश ने एक नया इतिहास रचा है।

उपार्जित गेहूँ के भुगतान की भी सरकार ने सुनिश्चित व्यवस्था की। अभी तक लगभग 25 हजार करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में पहुँच चुकी है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस वर्ष गेहूँ उपार्जन कर किसानों को प्राथमिकता के आधार पर राशि दी गई। जिसमें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को गति मिली। गेहूँ उपार्जन की प्रकिया में छोटे–छोटे भूखंड पर खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को सबसे पहले सीधे लाभान्वित करने में सफलता मिली।

पिछली सरकार ने खरीफ

और रबी फसलों के लिए फसल बीमा प्रीमियम की राशि 2200 करोड़ रूपयें का भुगतान बीमा कंपनियों को नहीं किया था। जिसके कारण किसानों को बीमा राशि नही मिल रही थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमा राशि भुगतान करने का निर्णय लिया और इसके फलस्वरूप किसानों को 2900 करोड़ रूपये की बीमा राशि मिली। मध्यप्रदेश सरकार ने फसल कटाई के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण देने की योजना फिर शुरू की गई। चना, मूंग, उड़द की भी सरकारी खरीदी की गई।

रोजगार सेतु पोर्टल से 16 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को मिला रोजगार

भोपाल। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अनेक माध्यम विकसित किये गये। इन माध्यमों में मनरेगा के साथ–साथ रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया। श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नियोक्ताओं को भी पोर्टल से जोड़ा गया। इस पोर्टल से अब तक 16 हजार 41 प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

रोजगार पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों के साथ ही नियोक्ता संस्थाओं ने भी पंजीयन करवाया है। पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या 25 हजार 247 हो चुकी है, जिनके द्वारा 29 हजार 170 रिक्तियाँ प्रवासी श्रमिकों के लिये खोली गई हैं। रोजगार सेतु पोर्टल के अलावा मनरेगा में 3 लाख 54 हजार 268 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया है।

राज्य सरकार ने गरीब प्रवासी मजदूरों को संबल पोर्टल में दर्ज कर उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता पहुँचाई जा रही है। संबल पोर्टल पर 3 लाख 24 हजार 715 श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके साथ ही आत्म–निर्भर भारत एवं राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून में 13 लाख 10 हजार 186 व्यक्तियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शाला में प्रवेश करवाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया गया। ऐसे 75 हजार 385 बच्चों को विभिन्न शासकीय शालाओं में प्रवेश की प्रक्रिया की गई।

मंत्री श्री पटेल ने खरगोन की फल–सब्जी मंडी का किया ई–शुभारंभ

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खरगोन जिले की बलवाड़ी मंडी के नवनिर्मित अतिरिक्त प्रांगण का ई–लोकार्पण और फल–सब्जी मंडी का ई–शुभारंभ किया।

मंत्री श्री पटेल ने 8 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से प्रथम चरण के पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण भी किया है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ की लागत से द्वितीय चरण के कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि फल–सब्जी मंडी का शुभारंभ होने से फल और सब्जी विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। अब वे बेहतर तरीके से अपना व्यापार कर सकेंगे। इस अवसर खरगोन में क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री बालकृष्ण पाटीदार, विधायक श्री रवि जोशी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री विपिन गौर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में 25 करोड़ का प्रावधान

भोपाल। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में शहरी पथ व्यवसाइयों एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संचालन के लिये विभागीय बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत पथ व्यवसाइयों को दिये जाने वाले 10 हजार के लोन पर केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले 7 प्रतिशत ब्याज, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, के अतिरिक्त ब्याज का वहन राज्य शासन करेगा। यह प्रावधान योजना की अवधि मार्च, 2022 तक जारी रहेगा।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी जिम्मेदारी तय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा में दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कांन्फ्रेन्स द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी भी स्थिति में अपराध सहन नहीं होंगे। श्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार और दोषी अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बिना किसी दवाब के काम करे। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना हुई तो टीआई, थानेदार ही नहीं वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि किसी की चिंता न करे, कोई अपराधियों को संरक्षण न दे। जो देगा उसे मैं देख लूंगा। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए भी सावधानी रखी जाए। कानून व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यदि ऑनलाइन अपराध हो रहे है, उस पर भी ध्यान दिया जाए, दूसरे राज्यों से अपराध होते है तो वहाँ के अधिकारियों का सहयोग अपराध खत्म करने में लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है, यहाँ अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों को क्रश करें, अपराधियो में पुलिस का ख़ौफ़ रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि बदमाशों की सूची बनाइये। ये समाज के दुश्मन हैं। इन पर सख्त कार्यवाही की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानसून का आगमन हो चुका है ऐसी स्थिति में कुछ जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को बाढ़ से बचाएं, इसके लिए जिला प्रशासन आवश्यक प्रबंध करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के नाम पर कुछ लोग वित्तीय अपराध भी कर रहे, इन्हे रोकें और माफिया, चिट फंड वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक होगी।

अपराधियों की संपत्ति जप्त करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जहाँ भी आवश्यक हो, अपराधियों की संपत्ति जप्त करने की कार्यवाही की जाए। पूर्व वर्षों में ऐसी कार्यवाही की गई है। इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाये।

सबकी चिन्ता-सबका सहयोग

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रदेश में "परहित सरिस धर्म नहिं भाई" के सिद्धांत पर काम कर रही है। कोरोना संकटकाल में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य सरकार का सिर्फ यही मकसद है कि प्रदेशवासियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, विशेषकर गरीब तबके, किसान, दिहाड़ी मजदूर, महिलाओं और विशेष पिछडे इलाकों के रहवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही संबंधित विभागों की समीक्षा कर प्रदेशवासियों को हर संभव सुविधायें पिछले तीन माह में उपलब्ध करवाई हैं। अल्प अवधि राजकीय कोष को चौतरफा खोल समाज के प्रत्येक वर्ग को सहायता पहुंचाकर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केवल उदारता का परिचय दिया बल्कि एक मिसाल कायम कर महानायक के रूप में पुनरू अपनी पहचान स्थापित की।

जब कोरोना संक्रमण का असर मध्यप्रदेश में बढ़ रहा था, तब श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मुखिया की कमान संभाली। श्री चौहान के सामने यह मुश्किल घड़ी थी, जिसे उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकारते हुए प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लिये और उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया। उनके ये प्रयास अभी भी निरंतर जारी हैं।

प्रदेश की जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान को कुछ ऐसे कठिन निर्णय भी लेने पड़े, जिनसे आमजनता को परेशानी तो महसूस हुई होगी, लेकिन उनका और उनके परिवार का जीवन सुरक्षित रहा। कोरोना का संकट जैसे– जैसे अपने पैर फैला रहा था, सरकार के लिये मुसीबत भी बढ़ती जा रही थी। इन परिस्थितियों से घबड़ाये बिना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपनी प्रशासनिक सूझ–बूझ का परिचय देते हुए मध्यप्रदेश को सुरक्षित रखने में अहम् सफलता प्राप्त की। मंत्रिमण्डल के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, धार्मिक गुरूओं और विभागीय अधिकारियों से सतत सम्पर्क बना कर कोरोना संकट से निपटने की पहल की जाती रही है। श्री चौहान ने समाज के हर तबके के साथ संवाद बनाये रखा और उनकी समस्याओं को जानकर उनका निराकरण भी किया।

कोरोनाकाल व सहकारिता

वैश्विक आपदा कोरोना से भारत भी प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के चरणों में गतिविधियॉ थम सी गई। इस समय स्वास्थ्य रक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता रही। कोरोना की कोई प्रभावी दवाई अभी नहीं होने से व कोरोना का प्रभाव लम्बा खिचता देख मजबूरन सरकार को अनलॉक के चरणों की घोषणा करनी पड़ी ताकि व्यवस्था पटरी पर लौट आये। इसी समय मौके का फायदा उठाकर चीन ने गलवान घाटी में सैन्य गतिविधियॉ बढ़ा दी। जिसके कारण सरकार को प्रतिउत्तर देने पर विवश होना पड़ा। सरकार ने चीन की कई कम्पनियों के अनुबंध समाप्त कर दिये व कई मोबाईल एप प्रतिबंधित कर दिये। देश में चीन व चीनी सामान के प्रति नाराजगी का भाव है। सरकार ने भी लोकल को वोकल का नारा दिया है।

कहा जाता है कि विपदा में अवसर भी छिपा रहता है। कोरोना व चीन के कारण कई नई बातों व व्यवसाय का उदय हुआ। मास्क, सेनिटाईजर व दो गज की दूरी आम बात हो गई। भारतीय सामानों की पूछ परख बढ़ गई। सहकारिता आंदोलन भारत में शुद्ध स्वदेशी है। इसमें विदेशी कम्पनियों का योगदान नगण्य है। भारत में सहकारिता के उत्पाद जैसे अमूल, इफको, कृभको, लिज्जत, हर्बल आदि पूर्ण स्वदेशी व गुणवत्तापूर्ण है। इस समय सहकारी उत्पादों के लिये व्यवसाय की अपार सम्भावना है। कोरोना से संबंधी हर्बल प्रॉडक्ट, मास्क, ग्लबज, केप, सेनेटाईजर, पीपीई किट आदि का उत्पादन व बिक्री सहकारिता के माध्यम से किया जाकर मुनाफा कमाया जा सकता है। ऑनलाईन बिक्री के युग में बहुत कम सहकारी उत्पाद ऑनलाईन बिक्री हेतु उपलब्ध है। इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के समय शहरों में सर्वाधिक मांग अनाज, फल, सब्जी व दूध की रही लेकिन उसकी उपलब्धता कम होने से कीमतों में तेजी देखने में आई। दूसरी और इनके उत्पादक ग्रामीण इलाके जो सहकारिता के अंर्तगत आते है वहां इनकी अधिकता के कारण भाव में कमी व नुकसान भी देखने में आया। यह स्थिति सभी के लिये नुकसानदेयक रही जिस पर सरकार को विचार कर भविष्य के लिये कार्ययोजना बनानी चाहिये।

डिजीटल इंडिया के जमाने में सहकारी क्षैत्र अभी पीछे नजर आता है। जो सुविधायें सरकारी व निजी क्षैत्रों द्वारा ग्राहकों को दी जा रही है उसमें सहकारिता पिछड़ रही है। जिसके कारण ग्राहकों की प्राथमिकता के क्रम में सहकारिता बाद में आता है। यह स्थिति ठीक नहीं है व इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। सहकारिता के ग्राहकों में अधिकतर कम पढ़ी लिखी व ग्रामीण आबादी आती है, जिनमें डिजीटल जागरूकता का अभाव है। इसके लिये सहकारिता को ही आगे आकर अपने ग्राहकों को प्रशिक्षित करना होगा। कोरोनाकाल में यह आवश्यक है कि जो भी कार्य ऑनलाईन हो सकते है उसके लिये ग्राहक संस्था में आकर जोखिम न उठाये व भीड न बढ़ायें।

सरकार द्वारा किसी भी आपदा में नागरिकों के लिये जो माफी व छूट का ऐलान किया जाता है उसका सीधा असर सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता है। अतः सरकार द्वारा संस्थाओं को क्षतिपूर्ति राशि समय पर दिये जाने की आवश्यकता है। जय सहकारिता।

शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक, इन्दौर

परियोजना क्रियान्वयन में अंतर्विभागीय समन्वय के लिये उच्च स्तरीय समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में गति लाने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने तथा परियोजनाओं में राज्य शासन की ओर से विभिन्न अनुमतियों तथा अनापत्तियों की अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम रहेंगे। वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में सचिव खनिज साधन विकास, क्षेत्रीय अधिकारी (म.प्र. भोपाल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, क्षेत्रीय अधिकारी (म.प्र. भोपाल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग समिति के सदस्य बनाये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से प्रदेश की जनता के पूरे परिश्रम से जुट जाने का किया आव्हान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर समस्त मंत्रियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनसे राज्य की जनता के हित में पूरे परिश्रम से जुटकर कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश की जनता का कल्याण सुनिश्चित करें। कोरोना से लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था भी धीरे–धीरे ठीक होगी और मध्यप्रदेश को बदलने में समय नहीं लगेगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने गत तीन माह में राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश में कोविड–19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रजेंटेशन द्वारा दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए हमें कार्य करना है। हम अपने लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए पूरी योग्यता, परिश्रम और तनमयता से कार्य करें। मुझे आशा है कि समस्त मंत्रीगण सौंपे गए उत्तरदायित्व को कर्मठता से पूरा करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि मेहनत की पराकाष्ठा हो, पारदर्शिता हो और प्रमाणिकता भी स्थापित हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें टीम के रूप में कार्य करना है। मौजूदा कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। इसके बावजूद हम पूरी क्षमताओं से, आनंद और प्रसन्नता के साथ कार्य करें। स्नेह सौजन्य मित्रता, सहयोग की भावना के साथ खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रदेश की जनता को स्वस्थ्य रखने और उन्हें विकास का लाभ पहुँचाने के पूरे प्रयत्न करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर जानकारी दी कि प्रत्येक मंगलवार को मंत्रि–परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने मंत्रीगण से अनुरोध किया कि सोमवार और मंगलवार को राजधानी भोपाल में रहकर कार्य निष्पादन करें।

मध्यप्रदेश में जन सहयोग से कोविड–19 के नियंत्रण में मिली है सफलता

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में कोविड–19 के नियंत्रण के प्रयास सफल हुए हैं। कोरोना पॉजीटिव रोगियों का निशुल्क उपचार शासकीय अस्पतालों और शासन द्वारा अनुबंधित निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। प्रदेश में आईआईटीटी रणनीति के तहत कार्य हुआ है। सर्व प्रथम रोग की पहचान अर्थात आईडेंटिफिकेशन फिर रोगियों के लिए आईसोलेशन की व्यवस्था के प्रयास किए गए। टेस्टिंग क्षमता बढ़ाते हुए ट्रीटमेंट की समुचित कार्यवाही की गई। किल–कोरोना अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है इसके अंतर्गत घर–घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से आग्रह किया कि इस अभियान में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करें। आयुर्वेदिक काढ़े की उपयोगिता सिद्ध हुई है।

पंच-परमेश्वर से गाँव के विकास को मिली नई दिशा

अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच–परमेश्वर भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में आमजन की श्रद्धा और गाँव–गाँव में पुराने समय से स्थापित पंचायत–राज व्यवस्था का अनुपम उदाहरण रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसी अवधारणा के दृष्टिगत पंचायतों में सुदृढ़ ढाँचा तैयार करने में पंच–परमेश्वर योजना का सूत्रपात किया गया है।

मध्यप्रदेश में 23 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही ''कोविड–19'' जैसी महामारी से निपटने के महा–अभियान की शुरूआत भी हुई है। 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों और 55 हजार से अधिक गाँव वाले इस राज्य में 2 तिहाई आबादी गाँव में ही निवास करती है। इन परिस्थितियों, इतनी आबादी और पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय बनाना एक बड़ी चुनौती थी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 (नियंत्रित करने) के लिए बहु–आयामी रणनीति पर काम किया गया। इसका परिणाम है कि मध्यप्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या कम रही है।

ग्रामीण अंचल में कोरोना से लड़ने तथा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में ''पंच–परमेश्वर योजना'' वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 जून को 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रूपये की राशि ग्राम पंचायतों को जारी की। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ राशि मिलने से ग्राम–पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। प्रदेश में औसतन 7 से 8 लाख रूपये की राशि एक ग्राम–पंचायत के खाते में पहुँची है। राज्य सरकार ने ''पंच–परमेश्वर'' योजना की गाइडलाइन में भी ग्राम–पंचायतों को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता दी।

कोरोना संक्रमण के इस दौर में ग्राम–पंचायतों के सामने मुख्य चुनौती थी गाँव और ग्रामीणों को कोरोना के संक्रमण से बचाना, गाँव में स्वच्छ पेयजल और अधोसंरचना को सुदृढ़ करना। ''पंच–परमेश्वर'' योजना 14वें वित्त की राशि में 2.5 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के सेनिटाईजेशन, ग्रामीणों और प्रवासी मजदूरों को मास्क उपलब्ध कराने पर व्यय की अनुमति दी गई। ग्राम–पंचायतों में अधोसंरचना विकास के सारे काम पुनरू शुरू हो चुके हैं जो स्थानीय रोजगार का माध्यम भी

बन रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में बड़ी तादाद में श्रमिकों की वापसी प्रदेश में हुई है। इसके साथ ही ऐसे श्रमिक भी हैं जो लॉक–डाउन के कारण अपने गृह–प्रदेश नहीं लौट पाये, उन्हें भी रोजगार मुहैया कराने का काम मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। 20 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े रोजगार पुनरू प्रारम्भ करने की गाइड लाइन जारी की गई।

अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोयेगा मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोयेगा।

– दीदी शिवानी

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के क्रियान्वयन के लिये समिति गठित

भोपाल। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएम एसवाय) के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिये शासन द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (एसएलए एमसी) का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग हैं। समिति में 6 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति अध्यक्ष द्वारा मत्स्य पालन से संबद्ध 2 सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार अन्य राज्य स्तरीय शासकीय कर्मियों को समिति के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकेंगे। संचालक मत्स्य उद्योग मध्यप्रदेश समिति के सदस्य सचिव नियुक्त किये गये हैं।

राज्य स्तरीय समिति जिलों से प्राप्त मत्स्य पालन की वार्षिक कार्य–योजना के आधार पर प्रदेश की कार्य–योजना बनाकर अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को अनुशंसा सहित अग्रेषित करेगी। यह समिति राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी। समिति योजना की गतिविधियों का राज्य स्तरीय अन्य योजनाओं और गतिविधियों के साथ कन्वर्जन्स कराने का कार्य भी करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के हितग्राही मूलक उप–घटकों/ गति–विधियों के सुगम क्रियान्वयन के लिये बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ लिंक कराने का काम भी समिति द्वारा किया जायेगा।

चम्बल एक्सप्रेस-वे के लिए 781 करोड़ स्वीकृत

अब चम्बल एक्सप्रेस–वे नहीं, चम्बल प्रोग्रेस–वे है – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल एक्सप्रेस–वे के बनने से प्रदेश के बीहड़ एवं पिछड़े क्षेत्र को औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट को ''चम्बल एक्सप्रेस–वे'' नहीं ''चम्बल प्रोग्रेस–वे'' के रूप में देखते हैं। केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी चंबल एक्सप्रेस–वे पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें भारतमाला के अंतर्गत मात्र 50 प्रतिशत भूमि निरूशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 421 करोड़ की 100 प्रतिशत भूमि निरूशुल्क उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में मिट्टी एवं मुरम की रायल्टी के रूप में 330 करोड़ प्रदान करेगा और वन भूमि की अनुमतियों पर होने वाले व्यय के रूप में 30 करोड़ का व्यय भी स्वयं वहन करेगा। इस प्रकार राज्य शासन 781 करोड़ का सहयोग प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि ''एक्सप्रेस वे'' प्रदेश में 309 किलोमीटर लंबा होगा। यह श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। यह मार्ग भिण्ड में गोल्डन क्वाड्रिलेट्रल (आगरा–कानपुर) मार्ग, मुरैना में नार्थ–साउथ कॉरीडोर एवं राजस्थान में दिल्ली मुम्बई कॉरीडोर से जोड़ा जायेगा। आवागमन का मार्ग सहज एवं सुविधाजनक होने से क्षेत्र को औद्योगिक निवेश प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आर्थिक/औद्योगिक विकास के लिए रक्षा उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्ष 2017 में भी की थी। एक्सप्रेस–वे के बनने से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास में बहुत मदद मिलेगी।

वीडियो कान्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चम्बल एक्सप्रेस–वे को भिण्ड–कोटा रेल्वे लाइन के साथ–साथ बनाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चम्बल एक्सप्रेस–वे के लिए हमारे पास 52 प्रतिशत सरकारी जमीन उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट के लिए शेष 48 प्रतिशत भूमि अदला–बदली मॉडल के तहत उपलब्ध करायी जायेगी। एलाइनमेंट होते ही यह जमीन निर्माण कार्य के लिए सौंप दी जायेगी। वीडियो कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नर्मदा जल का पूरा उपयोग किया जाएगा

भोपाल। मध्यप्रदेश को आंवटित 18.25 एमएएफ नर्मदा जल के उपयोग के लिए नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लगभग 32 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाएँ निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 19 हजार करोडं रूपये लागत की 9 परियोजनाओं की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मध्यप्रदेश को आबंटित नर्मदा जल का अधिकतम उपयोग हो सकेगा।

निर्माणाधीन परियोजनाओं में इंदिरा सागर परियोजना नहर, ओंकारेश्वर परियोजना नहर, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी व प्रवर्तन परियोजना तथा लोवर गोई परियोजना मुख्य है। इनके अलावा नर्मदा–मालवा गंभीर लिंक परियोजना उज्जैन देवास उज्जैनी पाईप लाईन तथा अपरबेदा आरबीसी के कार्य पूर्णतारू की ओर है।

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता को आगामी वर्षों में बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 33 लाख 77 हजार हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता को 2024–25 तक 50 लाख 74 हजार हेक्टेयर किया जाना है। वर्ष 2020 –21 में इसे 1.94 लाख हेक्टेयर, 21 –22 में 1.86 लाख हेक्टेयर, 22 –23 में 2.74 लाख हेक्टेयर, 23–24 में 5.76 लाख हेक्टेयर और 24 –25 में 4.66 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पूर्व में मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गेहूँ उपार्जन में रिकार्ड के बाद...

भारत की सस्ती सौर ऊर्जा की पूरी दुनिया में चर्चा है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम विश्व के टॉप 5 देशों में पहुँच गये हैं। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण दोनों की दृष्टि से लाभदायी है। वर्ष 2014 में जहां सौर ऊर्जा की कीमत 7 से 8 रूपये प्रति यूनिट हुआ करती थी, आज वह घटकर 2.25 से 2.50 रूपये प्रति यूनिट हो गयी है। रीवा सोलर प्लांट के माध्यम से सस्ती बिजली का उत्पादन बड़ी उपलब्धि है। सोलर बिजली की आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लिये आवश्यक है।

साफ–सुथरी ऊर्जा के प्रति हम संकल्पित

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हम संकल्पित है। हमें पर्यावरण की सुरक्षा तो करना ही है, साथ ही जनजीवन को आसान भी बनाना है। हमने हर घर में एलपीजी, सीएनजी आधारित वाहन व्यवस्था तो की ही है, अब बिजली आधारित परिवहन की व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे है। देश में गत वर्षों 36 करोड़ एलईडी बल्ब के माध्यम से लगभग 600 अरब यूनिट बिजली बचाई गई है। हमारा ध्येय है हर व्यक्ति तक सस्ती बिजली पहुँचे तथा वातावरण हवा पानी भी शुद्ध बना रहे।

मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण के प्रभावी उपाय

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण के प्रभावी उपाय किये है। उन्होंने कहा कि थोड़े से प्रयासों दो गज की दूरी चहरे पर मास्क लगाना, हाथ को 20 सेकण्ड तक साबुन से धोना, जगह–जगह नहीं थूकना आदि के माध्यम से हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी को आसानी से हरा सकते है। नियमों का पालन करें तथा अनुशासन में कमी न आने दें।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ''मैन ऑफ आईडियास'' हैं तथा उनकी प्रेरणा एवं दूरदृष्टि से ही हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही यह जान लिया था कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है तथा इस क्षेत्र में प्रभावी कार्य प्रारंभ कर दिये थे। मध्यप्रदेश में वर्ष 2010 में इसके लिये हमने नया विभाग बनाया। एशिया की सबसे बड़ी सोलर इकाई का नीमच में शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा ही किया गया। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही वर्ष 2017 में रीवा सोलर प्लांट का कार्य ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। ''मैं प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।''

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमेप तैयार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत की योजना को मूर्त रूप देने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार कर लिया गया है तथा उस पर तत्परता से अमल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के लिये सरहानीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश के 14 जिलें इसमें शामिल किये गये हैं। ग्वालियर–चंबल क्षेत्र में चंबल एक्सप्रेस–वे के माध्यम से प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसके लिये पूरा प्रदेश हृदय से आभारी है।

प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण सहित अन्य कार्यों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के वक्तव्य को ध्यान से सुना तथा अंत में ताली बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थिति थे। कार्यक्रम का संचालन, स्वागत भाषण एवं आभार प्रदर्शन प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे द्वारा किया गया।

एकल नागरिक डाटाबेस नागरिकों के लिए होगा अत्यंत लाभदायी

विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए एक ही स्थान पर मिल जाएगी पूरी जानकारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस पर कार्य किया जा रहा है। यह नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके बन जाने से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को अलग–अलग योजना के लिए बार–बार जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। एकल नागरिक डाटाबेस में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के लिए किया जा सकेगा।

नागरिकों को त्वरित लाभ मिलेगा, शासन का समय बचेगा

एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों से जानकारियाँ प्राप्त करने में लगने वाला समय बचेगा, जिससे कि योजनाओं का त्वरित लाभ देने में आसानी होगी। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 700 हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं, जिनका लाभ देने के लिए हितग्राहियों का पृथक–पृथक पंजीयन करना होता है।

स्कूलों में प्रवेश आदि के लिए नहीं मांगने होंगे दस्तावेज

एकल नागरिक डाटाबेस तैयार होने जाने से अजा–अजजा, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति आदि के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि नहीं मांगने होंगे। एकल नागरिक डाटाबेस में उनका सारा रिकार्ड पहले से ही दर्ज होगा। इससे एक ओर जहां विद्यार्थियों को सुविधा होगी, वहीं बहुत सा समय बचेगा।

ऐसे बनेगा एकल नागरिक डाटाबेस

एकल नागरिक डाटाबेस बनाने के लिए शासन के विभिन्न डाटाबेस समग्र आई.डी., भूमि रिकार्ड, वोटर आई.डी, आधार रिकार्ड आदि का एकीकरण किया जाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के डाटा को निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

अन्य राज्यों में भी एकल नागरिक डाटाबेस

राजस्थान में ''भामा शाह योजना'' के नाम से एकल नागरिक डाटाबेस लागू है। इसी प्रकार आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में इसे ''प्रजा साधिकार'' का नाम दिया गया है।

ये जानकारियां होंगी

एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक का नाम, उम्र, पता, आय, भूमि रिकार्ड, वाहन रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, अधिवास, निर्वाचन संबंधी, फसल, बीमा संबंधी जानकारी, बैंक ऋण, ड्राइविंग लायसेंस, छात्रवृत्ति, कौशल, रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि संबंधी जानकारियाँ होंगी।

क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं हैं। बुद्धिमान् व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।

– स्वामी विवेकानंद

मानसून काल में भी मिलेगा मनरेगा से रोजगार

भोपाल। महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मानसून काल में श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो सकेगा। इसके लिये साढ़े 13 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। मानसून काल में मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित लेबर बजट में बढ़ोतरी कर सभी जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में वापस लौटे प्रवासी लौटकर आए श्रमिकों तथा पूर्व से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन किया गया है। प्रदेश में वित्तिय वर्ष 2020–21 में पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20.50 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ऐसे सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। मानसून अवधि में वृक्षारोपण के तहत सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, निजी भूमि पर फलोद्यान, मंदिर कुंज, हैबिटेट रेस्टोरेशन जैसे कार्य कराने तथा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के तहत कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेकडेम, गोबियन संरचना जैसे कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्व–सहायता समूह के लिए कैटल शेड, गोट सेट, पोल्ट्री सेट जैसी संरचना स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकेंगी। गांव में चारागाह विकास के कार्य भी प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गये हैं।

गेहूँ की रिकार्ड खरीद

ठीक मार्च महीने के पहले मध्यप्रदेश के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने को मिल रही थी चिंता जायज भी थी जब अफवाहें अपने चरम पे थी कि इस बार मंडियों में गेहूं किस प्रकार तौला जाएगा। कोविड 19 की भयावह तस्वीरों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सचमुच चिंता में डाल दिया था कि गेहूं तौलना तो दूर खरीदेगा कौन? व्यापारी क्या बोली लगाने आएंगे? या इस परिस्थिति का फायदा उठा कर कहीं फसल के मूल्य से भी समझौता न करना पड़ जाएश

लेकिन खुशखबरी इंतजार कर रही थी बुधनी तहसील के ग्राम नांदनेर के किसान घनश्याम सिंह राजपूत ने फोन पर बताया कि उनका खलिहान में पड़ा गेहूं न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद लिया बल्कि वो अब मूंग की फसल पर भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उम्मीद से ज्यादा दिया है सभी किसान खुश है, इस अवधि में 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया गया है। प्रदेश के लिए यह ऑल टाइम रिकॉर्ड है। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश पंजाब को पछाड़ते हुए देश में पहले स्थान पर आ गया।

कोविड–19 की भयावह तस्वीरों के बीच सत्ता सम्हालने और इन सबके बीच गेहूं की फसल की चिंता कर लेना ही काफी नही था शायद, जो अचंभे में डालते हुए शिवराज सरकार ने आउट ऑफ दी बॉक्स जाकर गेहूं की खरीदारी में प्रदेश को पहले नम्बर पर ला कर खड़ा कर दिया और पंजाब जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी चुस्त–दुरुस्त सरकारी प्रणाली वाकई उनके राजनैतिक इच्छा शक्ति को न सिर्फ बतलाती है बल्कि उन लोगों का भी मुँह बंद कर देती है जो गेहूं की फसल को खलिहानों में ही सड़ जाने की आशंकाओं में दुबले हो रहे थे। वाकई ''इस बात पर सरकार को दाद देना तो बनता है'' शब्दो की कृपणता और आशंकाओं के पीछे छिप जाने जैसी विधाओं के बावजूद ये रिकॉर्ड तो कबीले तारीफ है। ग्राम बख्तरा के महेंद्र चौहान किसान है और गेंहू की फसल को लेकर चिंतित थे, फोन पर बात करने पर बताया कि बारदाने न होने की अफवाहों ने चिंतित कर दिया था क्योंकि साल भर की मेहनत का अच्छा खासा हिस्सा गेहूं की फसल पर लग जाता है लेकिन इस बार तमाम चिंताओं के बावजूद किसानों से न सिर्फ समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद लिया गया बल्कि सामान्य दिनों जैसी भी कोई समस्या नही आई। शिवराज सरकार का वापस आ जाना वरदान से कम नहीं है।

इस बार कोविड–19 के संक्रमण की वजह से गेहूं की खरीद 25 मार्च की जगह 15 अप्रैल से शुरू की गई थी। इस देरी से किसानों में मायूसी फैल गई थी और कई तरह की अटकलों से बाजार घनघनाने लगा था, कोरोना संक्रमण के कारण शारीरिक दूरी का खासा ध्यान रखना और संक्रमण न फैले ये भी एक बड़ा टास्क था जिसे बखूबी निभाया गया। किसी एक खरीदी केंद्र पर ज्यादा भीड़–भाड़ न हो और अराजकता जैसी स्थिति से बचने के लिए चार

हजार 529 केंद्र बनाकर खरीद की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार गेहूं उपार्जन की समीक्षा की और 23 मार्च से लगातार 75 मैराथन बैठकें लेते रहे।

एक व्यवहारिक चुनौती गेहूँ का सुरक्षित भंडारण किया जाना था जो कि स्पष्ट आदेशों और पक्की योजना के कारण सरकारी अमले ने आखिर ये भी कर ही दिखाया।

ज्यादा खरीदी केंद्र, ज्यादा खरीदारी– एक्सीक्यूशन की भाषा में इसे होरिजेंटल एक्सपैंशन कहा जाता है जिसमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए साधनों का फैलाव कर देते हैं और कम समयावधि में संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करते है। इस तकनीक से रिकॉर्ड खरीदी में बहुत ज्यादा फायदा हुआ और ये एक रिकॉर्ड बन पाया।

सरकार का वर्टिकल ढांचा इस बात को भांप गया था कि मंदी और आवागमन बंद होने के कारण पिछले साल की तुलना में कम अवधि में खरीद करनी होगी। इसके लिए उपार्जन केंद्रों की संख्या 3545 से बढ़ाकर 4,529 की गई। सबसे बड़ी चुनौती सात दिन में किसानों को भुगतान की व्यवस्था करना थी जो समय पर हो गई, इस प्रकार लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई।

सराहना इस बात की, की जाना चाहिए कि श्सरकारी अमले ने इस संख्या को सम्हालने की योजना भी तैयार कर रखी थीश और किसान को भुगतान किए जाने वाली रकम में भी कोई कमी नहीं आने दी गई। इस योजना के मल्टीपल लेयर की ठोस तैयारी और उसकी मॉनिटरिंग में कहीं भी कोई खबर नहीं पाते कि कहीं किसी भी प्रकार का हल्ला–गुल्ला हुआ हो।

14 लाख 22 हजार किसानों को ऐसे संकट के समय लगभग 25 हजार करोड़ का भुगतान किया गया जो इस बात की पुष्टि करता है कि कम से कम प्रदेश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं हुई।

लम्बे समय से राशन सामग्री न लेने वालों की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए कलेक्टर्स को निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को जून माह के राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही लंबे समय से राशन सामग्री न लेने वाले उपभोक्ताओं के नामों की समीक्षा करते हुए नए पात्र उपभोक्ताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कुछ जिलों से उपभोक्ता भंडार द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की स्थिति को समाप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पूर्व में मार्च, अप्रैल और मई माह का राशन प्रदान किया जा चुका है। कोविड–19 के संकट को देखते हुए सामग्री का अग्रिम प्रदाय भी किया गया। जून माह के लिए आवंटित खाद्यान्न के शत–प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को वितरण का कार्य पूरा किया जाए। प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि 88 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए गत दो माह बायोमेट्रिक पद्धति की अनिवार्यता भी समाप्त की गई। उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है। प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को खाद्य सामग्री का प्रदाय सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में नहीं होगी उर्वरक और खाद की कमी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक और खाद आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से आग्रह किया गया है।

श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिरिक्त उर्वरक प्राप्त करने के संबंध में यथासमय कार्यवाही पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव कृषि को इस संबंध में जरूरी फॉलोअप करने के निर्देश दिए। इसी तरह गत वर्ष उपार्जित 6.45 लाख मेट्रिक टन गेहूँ केन्द्रीय पूल में दिए जाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किए गए अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों से संवाद कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर सुझावों के लिए समिति गठित

भोपाल। विभागों की जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रकृति की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवाचारयुक्त समाधान, ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में उभरती हुई नवीनतम तकनीकों के माध्यम से प्राप्त करने के उद्देश्य से innovation.mp.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है। मध्यप्रदेश इनोवेशन पोर्टल पर प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

प्राप्त सुझावों के परीक्षण के लिए श्री अशोक शाह प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में छानबीन समिति का गठन किया गया है। इसमें श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव एमएसएमई, श्री धनराजू एस., संचालक कौशल विकास, श्रीमती छवि भारद्वाज, मिशन संचालक स्वास्थ्य मिशन समिति सदस्य और श्री एम. सेलवेन्द्रन, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सदस्य–सचिव नियुक्त किया गया है।

छानबीन समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के बाद प्राप्त सुझावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन/अनुमोदन समिति गठित की गई है। इसमें श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वित्त एवं श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को समिति का सदस्य और श्री एम. सेलवेन्द्रन, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सदस्य सचिव बनाया गया है।

कोरोना रोकथाम के लिए 27.51 करोड़ की आयुर्वेदिक दवा प्रदाय

भोपाल। प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिये राज्य लघु वनोपज संघ ने आयुष विभाग को 27 करोड़ 51 लाख 57 हजार रुपये मूल्य की आयुर्वेदिक औषधियों का प्रदाय किया है। आयुष विभाग द्वारा दिये गये कार्य आदेश पर लघु वनोपज संघ ने युद्ध स्तर पर औषधियों का उत्पादन किया, उसी गति के साथ आयुष विभाग ने जनसामान्य में कोरोना रक्षक औषधियों का निःशुल्क वितरण भी किया।

कोरोना प्रतिरोधात्मक औषधियों में त्रिकटू चूर्ण, अणु तेल, आरोग्य कसायम और संशमणि वटी शामिल है। इन औषधियों से खाँसी, बुखार, गला–नाक के संक्रमण ठीक होने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। भोपाल के बरखेड़ा पठानी स्थित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा प्रारंभिक लॉकडाउन अवधि में उच्च गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की आपूर्ति को निरंतर जारी रखने के साथ समय–सीमा में उच्च गुणवत्तायुक्त आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन कर कोरोना संकट काल में अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राज्य लघु वनोपज प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य असंगठित वनांचलों के लघु वनोपज संग्रहणकर्ताओं को लघु वनोपज का बाजार उपलब्ध करवाना और उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण रहा है।

किसानों को बोनी के पूर्व बीज और उर्वरक उपलब्ध कराएँ : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास कंपनियों की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। उन्होंने मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में है, किसानों को बोनी से पहले समय पर आवश्यकतानुसार उर्वरक और बीज उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश स्तरीय विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्नदाता किसानों को किसी भी प्रकार से खाद–बीज संबंधी कोई भी दिक्कत ना हो इसका भली–भांति ध्यान रखा जाए।

मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिए कि जहाँ से भी खाद–बीज का परिवहन हो रहा है या जहाँ पर उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जा रहे हैं, उन स्थानों से सैंपल लिए जा कर सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद–बीज ही उपलब्ध हो। खाद–बीज की सैम्पलिंग रिपोर्ट किसान के उपयोग के पूर्व आनी चाहिए।

मंत्री श्री पटेल ने बीज वितरण करने वाली कहा कि खाद–बीज अमानक पाए जाने पर भण्डार को लॉक किया जाए। श्री पटेल ने कीटनाशक की एक ही लैब से जानकारी मिलने पर निर्देश दिए कि अतिरिक्त लैब की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

मंत्री श्री पटेल ने चना उपार्जन कार्य की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का चना समर्थन मूल्य पर अभी तक उपार्जित नहीं हुआ है उन सभी को एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाए। आवश्यकतानुसार गांव में डोंडी पिटवाई जाए और सभी जिलों में प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा लोगों को अवगत कराया जाए कि सरकार के द्वारा प्रत्येक किसान का चना उपार्जित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का चना उपार्जित होने से छूटना नहीं चाहिए।

मंत्री श्री पटेल ने शिवपुरी–हरदा सोसायटी की जाँच रिपोर्ट 24 घंटे में प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित जिलों के कृषि उप संचालकों को दिए हैं।

अगले तीन वर्ष में किसानों के लिए 2 लाख सोलर पम्प स्थापित किये जाएंगे

भोपाल। प्रदेश में सोलर पम्प लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत किसानों के लिये अब–तक 14 हजार 250 सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। अगले तीन वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य है। सोलर पम्प से राज्य के किसानो कों सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा। सोलर पम्प लगाने से राज्य की बिजली कम्पनी पर भी भार कम होगा। सोलर पम्प का ये भी लाभ होगा कि ताप विद्युत पर निर्भरता कम होगी और यह पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के अंतर्गत किसानों को विशेष अनुदान देकर सस्ती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध करायें जाएंगे। इस योजना को सरलीकरण किया जा रहा है। किसानों को सोलर पम्प लगवाने में इससे सुविधा होगी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।